नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 081
दि. 23.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


# चार साल बाद स्थानीय लोकतंत्र की वापसी, महानगरपालिकाओं में चुनावी रण का औपचारिक शंखनाद

**(जीएनएस)**। मुंबई। करीब चार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में एक बार फिर स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने जा रही है। नगरसेवक बनने की चाह रखने वाले हजारों दावेदारों के लिए मंगलवार, 23 दिसंबर से मनपा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके साथ ही महानगरों की सियासत में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। 23 से 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार अपने-अपने प्रभागों के लिए तय जोन कार्यालयों से नामांकन पत्र खरीदकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मनपा प्रशासन ने 18 दिसंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके साथ ही औपचारिक रूप से चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो गया। अधिसूचना के अनुसार नामांकन आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण इन दो दिनों में नामांकन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी चरणों को पूरा करते हुए चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा।

नामांकन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की विधिवत जांच की जाएगी। इस दौरान दस्तावेजों में कमी या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नामांकन खारिज भी किए जा सकते हैं। वैध पाए गए उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशियों को 2 जनवरी तक अपना नामांकन वापस लेने का अवसर मिलेगा। 3 जनवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होने के साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्रचार का दौर शुरू होगा।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 15 जनवरी को कराया जाएगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतिम सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को करीब 13 दिनों का समय प्रचार के लिए मिलेगा। इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया लगभग 25 दिनों में पूरी की जाएगी। चार साल से अधिक समय बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय निकाय लंबे समय से प्रशासकों के भरोसे चल रहे थे। इसी बीच बृहन्मुंबई नगर निगम के आगामी आम चुनाव 2025-26 की तैयारियों को लेकर नगर निगम मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रशासनिक तैयारियों, कानूनी प्रावधानों तथा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने की। उन्होंने चुनावों के लिए तैयार की गई कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और समाधान का भरोसा दिलाया।

भूषण गगरानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर प्रशासन और चुनाव तंत्र निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील की। उनका कहना था कि आचार संहिता का पालन न केवल चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाएगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूती देगा और चुनाव अवधि के दौरान एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करेगा।

बैठक में अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, विशेष चुनाव अधिकारी विजय बलमावर, उप आयुक्त मूल्यांकन एवं संग्रह विश्वास शंखवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने नामांकन दाखिल करने, आवेदनों की जांच, आपत्तियों के निपटारे, मतदाता जागरूकता अभियानों और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। दलों की ओर से उठाए गए सवालों पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी स्तर पर पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा।

बैठक का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच नियमित समन्वय बनाए रखा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनी रहे। चार साल के अंतराल के बाद हो रहे इन मनपा चुनावों को स्थानीय शासन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके जरिए एक बार फिर जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा और महानगरों की सत्ता जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में लौटेगी।

## लवासा प्रकरण में बड़ा न्यायिक मोड़, दो दशक पुराने विवाद पर हाईकोर्ट की मुहर, पवार परिवार को मिली कानूनी राहत

**(जीएनएस)**। पुणे। महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों से लंबे समय से जुड़ा लवासा हिल सिटी परियोजना का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार फैसला शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले के पक्ष में गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को इस बहुचर्चित परियोजना से जुड़े उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित अवैध मंजूरियों को लेकर शरद पवार और उनके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। इस फैसले के साथ ही पवार परिवार पर लंबे समय से लटक रही कानूनी आशंका को फिलहाल विराम लग गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अनखड़ की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि लवासा परियोजना से जुड़ा यह मामला लगभग बीस साल पुराना है और इतनी लंबी देरी के बाद आपराधिक जांच की मांग करना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं

माना जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि याचिकाकर्ता इससे पहले भी इसी तरह की मांग लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है, जिसे वर्ष 2022 में अत्यधिक देरी के आधार पर खारिज किया जा चुका था।

सुनवाई के दौरान शरद पवार और अन्य नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने अदालत को बताया कि वर्तमान याचिका में वही पुराने आरोप दोहराए गए हैं, जिन पर पहले ही न्यायिक विचार हो चुका है। उनका तर्क था कि बिना किसी नए तथ्य या साक्ष्य के बार-बार एक ही मुद्दे को उठाना न तो कानूनसम्मत है और न ही न्याय के हित में। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक जांच का आदेश देने से पहले ठोस कानूनी आधार और विश्वसनीय सामग्री होना अनिवार्य है, जो इस मामले में अनुपस्थित है। याचिकाकर्ता नानासाहेब जाधव का आरोप था कि पुणे जिले के मुलशी घाट क्षेत्र में लवासा हिल सिटी परियोजना को मंजूरी देते समय नियमों की अनदेखी की गई और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। उनका दावा था कि उन्होंने वर्ष 2018 में पुणे पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कथित तौर पर बड़े राजनीतिक नाम जुड़े होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी आधार पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो सके। हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि केवल आरोपों के आधार पर जांच एजेंसी बदलने का आदेश नहीं दिया जा सकता। लवासा हिल सिटी परियोजना को कभी देश के पहले निजी हिल स्टेशन के रूप में पेश किया गया था। पुणे के पास वरसगांव बांध क्षेत्र में लगभग 25,000 एकड़ भूमि पर इस भव्य परियोजना की परिकल्पना की गई थी। बड़े-बड़े सपनों और निवेश के साथ शुरू हुई यह परियोजना उस समय विवादों में घिर गई, जब वर्ष 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। इसके बाद कानूनी अड़चनों, कर्ज के बोझ और प्रशासनिक विवादों ने इस परियोजना की गति पूरी तरह थाम दी। बीते वर्षों में लवासा परियोजना को लेकर कई बार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हुए। वर्ष 2022 में हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने इस विवाद को और हवा दी थी, जिसमें कहा गया था कि इस परियोजना में शरद पवार और सुप्रिया सुले का 'व्यक्तिगत हित' और 'प्रभाव' नजर आता है। उस समय के सिंचाई मंत्री रहे अजित पवार पर भी प्रक्रियागत चूक के आरोप लगाए गए थे। हजारों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी यह परियोजना अंततः दिवालिया हो गई और आज यह इलाका एक अधूरी और लगभग खंडहर में तब्दील होती परियोजना के रूप में देखा जाता है।

## सेवा, संस्कार और स्मृति का सम्मान: पुरुषोत्तमदास पुरोहित के नाम डाक टिकट, पाली के इतिहास में दर्ज हुआ स्वर्णिम अध्याय

**(जीएनएस)**। पाली। पाली जिले के लिए यह क्षण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, परोपकार और सामाजिक समर्पण से भरे जीवन को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक बन गया है। बसंत गांव के भामाशाह, समाजसेवी और आदर्श होटल ग्रुप, मुंबई के संस्थापक स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास एच. पुरोहित के उल्लेखनीय सामाजिक और जनसेवा कार्यों के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनके नाम का डाक टिकट जारी किया गया है। यह डाक टिकट न सिर्फ स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोहित के जीवन कार्यों को अमर बनाता है, बल्कि पाली जिले के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह जिले के इतिहास में जारी होने वाला पहला डाक टिकट है।

इस ऐतिहासिक डाक टिकट का वीआईपी एलबम स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोहित के पुत्र घनश्याम पुरोहित और जगदीश पुरोहित ने पाली के सांसद पी. पी. चौधरी को उनके कार्यालय में भेंट किया। यह क्षण भावनाओं से भरा हुआ था, जहां एक ओर पिता की स्मृतियों और उनके आदर्शों का सम्मान था, वहीं दूसरी ओर आने

वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का संदेश भी निहित था। एलबम भेंट करते समय उपस्थित सभी लोगों ने इसे पाली की सामाजिक चेतना और प्रवासी समाज के योगदान की एक महत्वपूर्ण पहचान बताया।

इस अवसर पर सांसद पी. पी. चौधरी ने कहा कि भारत की प्रगति में प्रवासी समाज की भूमिका हमेशा से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। देश से बाहर या महानगरों में रहकर भी अपने मूल स्थान और समाज से जुड़कर सेवा कार्य करना, राष्ट्र निर्माण का ही एक रूप है। उन्होंने कहा कि स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोहित जैसे व्यक्तित्वों ने यह सिद्ध किया कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बन सकती है। सांसद ने पी. एच. पुरोहित (रावतसिंह) चैरिटेबल ट्रस्ट और आदर्श होटल ग्रुप, मुंबई द्वारा स्थापित स्व. सरोजदेवी पुरुषोत्तमदास पुरोहित राजकीय आरोग्य केंद्र, बसंत के सेवा कार्यों की विशेष सराहना की और कहा कि यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार बन चुका है। उन्होंने भविष्य में इसके विस्तार और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर भी सकारात्मक विचार व्यक्त किए। घनश्याम पुरोहित और जगदीश पुरोहित ने इस अवसर पर कहा कि उनके लिए यह डाक टिकट केवल एक सरकारी सम्मान नहीं, बल्कि उनके पिताश्री के सेवा, सादगी और मानवता से भरे जीवन की सार्वजनिक स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जीवनभर समाज के लिए काम किया और बिना किसी प्रचार के जरूरतमंदों की मदद को अपना कर्तव्य माना। परिवार का यह संकल्प है कि वे पिताश्री द्वारा दिखाए गए सेवा और संवेदना के मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अपने योगदान को और मजबूत करेंगे। डाक टिकट का जारी होना पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और यह आने वाली पीढ़ियों को समाजसेवा के लिए प्रेरित करेगा।

इस गरिमामय अवसर पर पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रधान पृथ्वीराज पुरोहित, आदर्श परिवार के विनोदकुमार, शिवसेना (शिंदे) के राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि स्व. पुरुषोत्तमदास पुरोहित का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर व्यक्ति समाज के लिए असाधारण कार्य कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान यह भावना बार-बार उभरकर सामने आई कि यह डाक टिकट केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरक संदेश है।

पाली जिले के इतिहास में दर्ज हुआ यह अध्याय न केवल एक व्यक्ति के सम्मान की कहानी है, बल्कि उस परंपरा का प्रतीक भी है जिसमें समाजसेवा, परोपकार और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता है।

## जनहित और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सख्त फैसला: दादरा एवं नगर हवेली में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध

**(जीएनएस)**। सिलवासा। दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने जनहित, पशु कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक अहम और दूरगामी निर्णय लिया है। जिले की सीमा में चाइनीज मांझे, जिसे सिंथेटिक पतंग डोर के नाम से जाना जाता है, के उपयोग, बिक्री, भंडारण, परिवहन और आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि नायलॉन, प्लास्टिक या धातु-लेपित सिंथेटिक मांझा आम नागरिकों, विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। बीते वर्षों में सामने आई कई दर्दनाक घटनाओं और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चाइनीज मांझा केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पक्षियों और पशुओं के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। पतंगबाजी के दौरान आसमान में फैला यह तेज धार वाला सिंथेटिक मांझा उड़ते हुए पक्षियों के पंख और गर्दन को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है या वे जीवनभर के लिए अपंग हो जाते हैं। कई बार आवारा पशु और पालतू जानवर भी जमीन पर गिरे मांझे में उलझकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसके अलावा सड़क पर दौड़ते दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मांझा किसी अदृश्य ब्लेड से कम नहीं है। गले, चेहरे और हाथों पर गंभीर कट लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं, जिनमें कई लोगों की जान तक चली गई।

प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया है कि चाइनीज मांझा नॉन-बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी यह लंबे समय तक नष्ट नहीं होता और पर्यावरण में बना रहता है। खेतों, जंगलों, नालों और जल स्रोतों में फंसा यह मांझा प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। बारिश के मौसम में यह नालियों और जल निकासी प्रणालियों को भी अवरुद्ध कर देता है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा होती है। इस प्रकार चाइनीज मांझा केवल एक मौसमी शौक का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संकट का कारण बनता जा रहा था।

प्रशासन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार पहले ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी समय-समय पर इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके, कई स्थानों पर चोरी-छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग जारी था, जिससे कानून के प्रति लापरवाही और जनसुरक्षा के प्रति उदासीनता सामने आ रही थी। दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जिले की सीमा में किसी भी कीमत पर चाइनीज मांझे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार के चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, जब्ती और अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल होंगे। प्रशासन ने संबंधित विभागों, पुलिस और नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से बाजारों, दुकानों और संभावित स्थानों पर निगरानी रखें और प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

प्रशासन ने इस अवसर पर नागरिकों से भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे पतंगबाजी के दौरान केवल सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सूती मांझे का ही उपयोग करें। सूती मांझा न केवल इंसानों और पशु-पक्षियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है।

## बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में उबाल, कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन

**(जीएनएस)**। कोलकाता। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखा उबाल देखने को मिल रहा है। सोमवार को इसका असर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस समय साफ नजर आया, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में दिपु चंद्र दास की कथित हत्या का मुद्दा उठाते हुए बांग्लादेशी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस तरह की घटनाओं को भारत कभी चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और दिपु चंद्र दास की हत्या ने इन आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दास को जिंदा जलाकर बेहद बेरहमी से मार दिया गया, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अधिकारी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भाजपा इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। भाजपा नेता ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी इस मुद्दे को केवल एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 24 दिसंबर को भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक घंटे का प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की ओर आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा 26 दिसंबर को एक बार फिर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाती और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर नारेबाजी की और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। माहौल पूरी तरह राजनीतिक और भावनात्मक था, जहां कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। भाजपा नेताओं का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर किया जा रहा है, और भारत जैसे पड़ोसी देश की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करे। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में बांग्लादेशी सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग का रिश्ता निभाया है, लेकिन यदि किसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस पर सवाल उठाना और विरोध करना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो सके।

इस प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर टीएमसी की भूमिका पर सवाल उठाए। अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति में उलझी हुई है।


नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

## संपादकीय

# चीन की कामयाबी से सबक ले रोकें प्रदूषण

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इस समय गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि इसके आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर और देश के अन्य कई शहरों में भी प्रदूषण का संकट आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। हालांकि दिल्ली की स्थिति सबसे गंभीर है, लेकिन पूरे देश में दीर्घकालीन योजना और ठोस नीतियों की आवश्यकता अनिवार्य है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई दिनों से 450 के आसपास बना हुआ है, जो कि गंभीर स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी देता है। दिल्ली सरकार ने कई उपाय किए हैं—वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक का उल्लंघन करने पर प्रवेश पर रोक, सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक आदि। इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में आशातीत कमी नहीं आई है। इस संकट को देखते हुए चीन के दूतावास ने भी मदद की पेशकश की है। चीन के बीजिंग में AQI 67 के स्तर पर है, जबकि दिल्ली में यह 447 के आसपास है। यह स्पष्ट करता है कि योजनाबद्ध और सख्त नीतियों के जरिए प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।

चीन ने पिछले दो दशकों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई ठोस और आक्रामक कदम उठाए हैं। बीजिंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण सख्ती से लागू किया गया, और ऑड-ईवन जैसी नीतियों से सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाई गई। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार किया गया। भारी उद्योगों को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों से हटाया गया, जिसमें कोयला आधारित संयंत्रों और स्टील फैक्ट्रियों का स्थानांतरण शामिल था। इस कदम से घातक कणों (PM 2.5 और PM 10) में 20 प्रतिशत की कमी आई।

बीजिंग ने निर्माण स्थलों पर धूल-रोधी जालियों का इस्तेमाल, पानी की छिड़काव-सफाई, किसानों को पराली जलाने पर जुर्माना या भत्ता देने जैसे उपाय किए। प्रदूषण के पीक समय में निर्माण कार्यों पर रोक, पौधारोपण और हरी ढाल बनाने जैसी नीतियों से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

हालांकि दिल्ली और बीजिंग की भौगोलिक स्थिति अलग है। दिल्ली एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, जिसके चारों ओर औद्योगिक और कृषि भूमि है, जबकि बीजिंग के आसपास समुद्री इलाका और खुली भूमि मौजूद है, जो वायु परिसंचरण में मदद करती है। फिर भी, बीजिंग मॉडल से कई सीख भारत लागू कर सकता है।

दिल्ली में दीर्घकालिक नीति के तहत कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स को राजधानी से बाहर स्थानांतरित करना चाहिए। दिल्ली की तीन सौ किमी की परिधि में 11 ऐसे पॉवर प्लांट हैं, जो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत करना होगा, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो। निर्माण स्थलों पर सख्त नियम लागू किए जाएं, धूल रोकने वाले जाल और पानी की छिड़काव जैसी नीतियां अपनाई जाएं। औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर ले जाने के लिए विशेष बजट और योजना बनानी होगी।

देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण गंभीर समस्या बन रहा है। लखनऊ, वाराणसी, पटना, जयपुर, मुजफ्फरपुर और कानपुर जैसे शहरों में औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों की बढ़ती संख्या, ठोस अपशिष्ट और पराली जलाने जैसी गतिविधियों के कारण वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है। इन शहरों के लिए भी दीर्घकालिक और सख्त नीतियों की आवश्यकता है। केवल दिल्ली या कुछ बड़े शहरों पर ध्यान देने से समग्र स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। सारांश में कहा जा सकता है कि दिल्ली और देश के शहरों में प्रदूषण की समस्या केवल वर्तमान स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। चीन के बीजिंग मॉडल से यह सीख ली जा सकती है कि योजनाबद्ध, आक्रामक और सतत नीतियों से शहरी प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भारत में भी सार्वजनिक परिवहन, उद्योग नियंत्रण, निर्माण स्थलों की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और हरित क्षेत्र विस्तार जैसी नीतियों को लागू कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, उद्योगों की जिम्मेदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए ही दीर्घकालिक समाधान संभव है। दिल्ली और देश के अन्य शहरों के लिए यह चुनौती स्पष्ट है—प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम, लंबी अवधि की योजना और सख्त निगरानी जरूरी है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय क्षति की समस्या और गंभीर रूप ले सकती है।

# निर्णायक फैसलों से बदलेगी दुनिया की तकदीर

> “अब वक्त है कि विश्व आर्थिक मंच को शक्ति दी जाए। दावोस में ऐसे निर्णय लिए जाएं जो दुनिया में व्यापार, उत्पादन और निवेश का रुख बदल दें। पिछड़े देशों की समस्याएं—महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी—के समाधान केवल पलायन में नहीं हैं।

पिछले कुछ दशकों में दुनिया का स्वरूप तेज़ी से बदला है। अब वैश्विक व्यवस्था केवल अमेरिका-पश्चिम और रूस जैसे दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रही। एक तीसरा प्रभावशाली समूह उभरा है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के वे देश शामिल हैं जिन्होंने उपनिवेशवाद से मुक्त होकर मेहनत, दूरदर्शी नेतृत्व और निवेश के बल पर अपनी पहचान बनाई है। यह बदलाव केवल तेल उत्पादक देशों तक सीमित नहीं है। इन उभरते राष्ट्रों में भारत प्रमुख है, जिसकी अनदेखी आज किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए संभव नहीं रही।

भारत में हुए जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी देशों की उभरती शक्ति को तीसरी दुनिया की नई ताकत के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। इसके बावजूद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने कई अंतरराष्ट्रीय मंच आज भी पुराने ढांचे में जकड़े हैं। यदि इन संस्थाओं को बदलते समय के अनुरूप ढाला जाए, तो वैश्विक व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन संभव है। आज दुनिया युद्ध, तनाव और पर्यावरण संकट जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। हथियार उत्पादक देश अपने व्यावसायिक हितों के लिए संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं, पर्यावरण प्रदूषण की जिम्मेदारी लेने से बड़े देश बचते हैं और इसे विकासशील देशों पर थोप देते हैं, जिससे वैश्विक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

अब एक महत्वपूर्ण अवसर सामने है—दावोस सम्मेलन। आगामी 19 से 23 जनवरी तक होने वाला यह विश्व का व्यापक प्रतिनिधित्व करने वाला आर्थिक सम्मेलन होगा, जिसमें 103

देशों के लगभग 3,000 वैश्विक नेता और 60 राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। भारत की इसमें व्यापक और उत्साहपूर्ण भागीदारी तय है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपति, कॉरपोरेट नेता, बैंकों के प्रमुख और सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। रिलायंस, टाटा, बजाज और भरतिया जैसे बड़े कारोबारी समूह भी भाग लेंगे। भारत से भी 100 से अधिक सीईओ दावोस जा रहे हैं।

जी-7 और जी-20 तथा ब्रिक्स देशों के साथ अन्य देशों के नेता व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। यह मंच तीसरी दुनिया की उभरती शक्ति, उसके उत्पादकों और निवेशकों को आगे लाने तथा वैश्विक आर्थिक अवरोधों पर ठोस चर्चा का सुनहरा अवसर है।

सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और कल्याण शाखाएं आज भी अमेरिका और अन्य समृद्ध देशों द्वारा ही निर्देशित क्यों होती हैं? आज वैश्विक मंच पर नए उभरते देशों के प्रतिनिधि इसमें क्यों शामिल नहीं किए जाते? भारत जैसी शक्ति के वैश्विक योगदान के बावजूद उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छठी वीटो पावर क्यों नहीं दी गई? अगर जी-20 का सम्मेलन भारत में नहीं होता, तो क्या अफ्रीकी देशों को उनका उचित स्थान संयुक्त राष्ट्र में मिल पाता? दरअसल, हकीकत यह है कि आज संयुक्त राष्ट्र क्रमशः निष्प्रभावी संस्था बनता जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जबकि लंबे समय से संघर्ष विराम के बावजूद इस्राइल और हमास का संघर्ष जारी है। इसमें अन्य इस्लामिक देश कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र सशक्त और निर्णायक होता, तो ये संहारक युद्ध निरंतर नहीं चलते। अब ये अंतरराष्ट्रीय मंच अति-समृद्ध देशों के नियंत्रण में कठपुतली बनते जा रहे हैं, और उभरती शक्तियों की वास्तविक क्षमता को न पहचानने के कारण निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। अब वक्त है कि विश्व आर्थिक मंच को शक्ति दी जाए। दावोस में ऐसे निर्णय लिए जाएं जो दुनिया में व्यापार, उत्पादन और निवेश का रुख बदल दें। पिछड़े देशों की समस्याएं—महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी—के समाधान केवल पलायन में नहीं हैं। इन देशों की युवा शक्ति का समुचित उपयोग जरूरी है। अब समय आ गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सामूहिक रूप से बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करें और नई सशक्त आवाज के साथ दुनिया के व्यापार और निवेश को प्रभावित करने वाली शक्तियों का सामना करें। भारत में इसके लिए तैयारी जारी है, और निजी क्षेत्र लगातार सचेत है। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के साथ तालमेल बैठाकर नई प्राथमिकताएँ अपनानी चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करना है। समृद्ध देश अभी तक इसमें जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं। दुनिया में आर्थिक मंदी के हालात लगातार बढ़ रहे हैं। दावोस का विश्व आर्थिक मंच केवल कल्पना नहीं, बल्कि निर्णायक फैसले लेकर नई आर्थिक दुनिया बनाने का अवसर है।

## प्रेरणा

# जब सवालों की भीड़ में सरल समझ सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है

कभी-कभी जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयाँ किसी भारी-भरकम दर्शन या मोटी किताबों में नहीं, बल्कि किसी गली-कोने, किसी मेहनतकश इंसान की सहज बातों में छिपी होती हैं। तेली और दार्शनिक की यह कथा भी कुछ ऐसी ही है, जो बाहर से देखने पर एक साधारण संवाद लगती है, लेकिन भीतर से वह हमारे सोचने के तरीके पर सीधा सवाल खड़ा करती है। यह कहानी बताती है कि हर स्थिति को तर्क की कसौटी पर कसना जरूरी नहीं होता और हर सवाल का जवाब शक में ढूंढना अकसर हमें सच्चाई से दूर ले जाता है।

तेली का कोल्हू चल रहा है, बैल घूम रहा है और काम अपनी गति से हो रहा है। इस पूरी व्यवस्था में न कोई जटिल गणित है, न कोई गूढ़ सिद्धांत। आंखों पर पट्टी, गले में घंटी और तेली की नींद—ये तीनों मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं, जो अनुभव की जमीन पर खड़ी है। तेली जानता है कि बैल की दुनिया कैसी होती है। उसे यह भी पता है कि बैल को अगर बार-बार यह एहसास कराया जाए कि वह एक ही जगह घूम रहा है, तो वह ऊब सकता है और रुक सकता है। इसलिए पट्टी है, इसलिए घंटी है और इसलिए तेली निश्चिंत होकर सो रहा है।

दार्शनिक का आना इस निश्चिंतता को हिला देता है। उसके सवाल मासूम नहीं हैं, वे तर्क से भरे हुए हैं। वह हर व्यवस्था में संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है—अगर बैल रुक गया तो? अगर तुम सो रहे हो तो कैसे जानोगे? अगर वह खड़ा रहकर गर्दन हिलाने लगा तो? उसके लिए हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जीवन हर “अगर” के सहारे नहीं चलता, बल्कि अधिकतर आदत, स्वभाव और भरोसे के सहारे आगे बढ़ता है। यहां असली टकराव तर्क और व्यवहार के बीच है। दार्शनिक का तर्क किताबों, कल्पनाओं और संभावनाओं से उपजा है, जबकि तेली का ज्ञान रोज़मर्रा की मेहनत और अनुभव से। तेली जानता है कि बैल चालाक नहीं होता, वह योजना नहीं बनाता, वह सिस्टम को चकमा देने की कोशिश नहीं करता। वह अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। दार्शनिक बैल को भी अपने जैसा मान बैठता है—सोचने वाला, चाल चलने वाला, अवसर तलाशने वाला। यही उसकी भूल है।

तेली का अंतिम जवाब—“यह बैल है, दार्शनिक नहीं”—केवल एक मज़ाकिया टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हर प्राणी, हर इंसान और हर परिस्थिति की अपनी सीमाएँ होती हैं। उन सीमाओं को न समझकर अगर हम हर जगह अत्यधिक चतुराई, साजिश और चालाकी ढूंढने लगें, तो हम जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना लेते हैं।

आज के समय में यह कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। हम रिश्तों में भी दार्शनिक बन जाते हैं, हर शब्द के पीछे अर्थ ढूंढते हैं, हर व्यवहार में चालाकी तलाशते हैं। परिणाम यह होता है कि विश्वास टूटता है और मानसिक शांति खत्म होती जाती है। जबकि जीवन का बड़ा हिस्सा तेली की तरह सहज समझ और साधारण भरोसे से बेहतर चलता है।

यह कथा यह नहीं कहती कि सोचो मत, सवाल मत करो या तर्क मत अपनाओ। बल्कि यह चेतावनी देती है कि तर्क जब अनुभव से कट जाता है, तो वह बोझ बन जाता है। जहां जरूरत हो वहां प्रश्न जरूरी हैं, लेकिन हर जगह प्रश्नचिह्न लगाना जीवन को थका देने वाला बना देता है। तेली इसलिए चैन से सो पाता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी व्यवस्था वास्तविकता पर आधारित है, कल्पनाओं पर नहीं।

तेली की नींद अपने आप में एक प्रतीक है—वह संतोष और आत्मविश्वास की नींद है। दार्शनिक शायद उस जगह होता तो पूरी रात जागकर यह सोचता रहता कि बैल अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा, वैसा कर दे तो क्या होगा। एक इंसान जीवन को जी रहा है, दूसरा उसे समझने की कोशिश में जीना भूल रहा है।

अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को चलाने के लिए हमेशा बड़े-बड़े सिद्धांतों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी थोड़ी समझ, थोड़ा अनुभव और थोड़ी सहजता ही सबसे मजबूत तर्क बन जाती है। और यह जान लेना कि हर बैल दार्शनिक नहीं होता, शायद हमें भी अपने जीवन में अनावश्यक सवालों से थोड़ी राहत दिला सकता है।

# ‘कालीन भैया’ से ‘कोडिन भइया’ तक, कफ सिरप बना यूपी की सियासत का नया अखाड़ा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है—कोडिन। खांसी की दवा में इस्तेमाल होने वाला कोडीन युक्त कफ सिरप अब सिर्फ स्वास्थ्य या कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे तीखी सियासी जंग का प्रतीक बन चुका है। मिर्जापुर के चर्चित कालीन भैया की तर्ज पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर में ‘कोडिन भइया’ का तंज कसकर योगी सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जड़ समाजवादी पार्टी से जुड़ी बताते हुए पलटवार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक पोस्टर वार, बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया।

दरअसल पूरा विवाद कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद, भंडारण और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा है। पिछले साल फरवरी में राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और विशेष कार्य बल को संयुक्त जांच के आदेश दिए थे। आरोप था कि कफ सिरप और कोडीन आधारित अन्य दवाओं को बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमा कर नशीले पदार्थों की तरह बेचा जा रहा है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, एक संगठित नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और नेपाल-बांग्लादेश की सीमाओं तक फैली नजर आईं।

मध्य प्रदेश स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से मिली अहम जानकारी के आधार पर दवा निरीक्षकों ने हिमाचल प्रदेश के दो, उत्तराखंड के तीन, हरियाणा के एक डिपो और झारखंड के रांची स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य स्टॉकधारक की जांच शुरू की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 279 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और कोडीन आधारित कफ सिरप के निर्माण, खरीद-बिक्री, भंडारण और वितरण से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि वाराणसी, गाजियाबाद और आसपास के इलाके इस नेटवर्क के प्रमुख केंद्र थे, जहां यह गतिविधि अन्य जिलों की तुलना में कहीं ज्यादा संगठित और नियमित थी।

एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले झारखंड की एक ऐसी कंपनी का पता चला जिसने कथित तौर पर एक बंद हो चुकी निर्माता कंपनी से करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य का कफ सिरप खरीदा था। यही सिरप झारखंड के रास्ते बांग्लादेश तक तस्करी किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि यह कंपनी कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा संचालित की जा रही थी। फर्जी बिल, कागजों पर मौजूद फर्में, गायब रजिस्टर और प्रॉक्सी लेनदेन—ये सब इस नेटवर्क की पहचान बनकर सामने आए। अधिकारियों का मानना है कि बड़ी मात्रा में हेराफेरी की गई ये दवाएं अवैध तस्करी नेटवर्क में प्रवेश कर रही थीं और लखनऊ, लखीमपुर खेरी, बहराइच से होते हुए नेपाल तक पहुंचाई जा रही थीं। इसी तरह वाराणसी और गाजियाबाद से बंगाल और बांग्लादेश तक के रास्ते भी सामने आए।

जैसे ही इस रैकेट से जुड़े कुछ नाम सामने आए, मामला राजनीति की आग में घी बन गया। शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की तस्वीरें जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। कई पोस्ट में धनंजय सिंह द्वारा इन तीनों को ‘छोटा भाई’ कहे जाने का दावा किया गया। खुद धनंजय सिंह ने अलग-अलग इंटरव्यू में इनके साथ अपने रिश्ते से इनकार नहीं किया, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें इस कथित सिंडिकेट की कोई जानकारी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने यहीं से सरकार पर हमला तेज कर दिया और आरोप लगाया कि धनंजय सिंह के जरिए आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है।

अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जैसे मिर्जापुर में कालीन भैया थे, वैसे ही जौनपुर में कोडिन भइया हैं। उनका इशारा किस ओर है, यह राजनीतिक गलियारों में किसी से छिपा नहीं रहा। अखिलेश ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो फिर इन आरोपियों के घरों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में और सार्वजनिक मंचों से इस हमले का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मामले की गहराई में जाएंगे तो घूम-फिरकर वही लोग सामने आएंगे, जिनका संबंध समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े लोगों से है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। सदन में चर्चा के दौरान योगी ने दिल्ली और यूपी की राजनीति की तुलना करते हुए विपक्ष पर तंज कसा और नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरोपियों की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ साझा कर सियासी हमला तेज कर दिया।

जांच की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर 18 अक्टूबर को सोनभद्र में दर्ज की थी, जब कोडीन कफ सिरप से भरे दो ट्रक पकड़े गए और मौके से एक लाख से ज्यादा बोतलें बरामद हुईं। पूछताछ में बड़े गिरोह के संकेत मिलने के बाद गाजियाबाद और सोनभद्र पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। गाजियाबाद में 15 लाख से अधिक बोतलें जब्त की गईं और कई गिरफ्तारियां हुईं। अब तक 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापे पड़ चुके हैं और 31 जिलों में 133 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई हैं। वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, महाराजगंज जैसे जिले इस कार्रवाई के केंद्र में हैं।

कुल मिलाकर कोडिन कफ सिरप का मामला अब सिर्फ कानून-व्यवस्था या ड्रग्स तस्करी का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। ‘कालीन भैया’ से ‘कोडिन भइया’ तक पहुंची यह जंग आने वाले समय में और तेज होने के संकेत दे रही है, जहां जांच की हर नई परत के साथ सियासत की धार और पैनी होती जा रही है।

## अभियान

# जब प्रेम स्वयं प्रेम को जानने चला

भक्ति की कथाओं में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, जो केवल कथा नहीं रह जाते, बल्कि साधक के भीतर उतरकर प्रेम, विरह और आत्मविस्मरण का गहरा अनुभव करा देते हैं। राधा और कृष्ण का यह संवाद भी ऐसा ही है, जहां ईश्वर और प्रेमिका आमने-सामने हैं, लेकिन प्रश्न साधारण नहीं, अस्तित्व के रहस्य से जुड़े हुए हैं।

एक बार निकुञ्ज में राधा जी श्रीकृष्ण से मिलने आईं। वातावरण में वही शाश्वत माधुर्य था—वृंदावन की हवा, यमुना की शीतलता और प्रेम की मौन तरंगें। राधा जी ने सहज भाव से श्रीकृष्ण से पूछा, “तुम बांसुरी क्यों बजाते हो?” कृष्ण मुस्कराए और सरलता से बोले, “तुम्हें बुलाने के लिए।” यह उत्तर सुनकर राधा जी के हृदय का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, “जब तुम बांसुरी बजाते हो, तब मैं सब कुछ भूल जाती हूं। लोक, लाज, कर्तव्य, संसार—सब पीछे छूट जाता है और मैं बिना सोचे तुम्हारी ओर भाग आती हूं।”

कृष्ण ने मानो जिज्ञासा से पूछा, “ऐसा क्या है मेरी इस बांसुरी में?” राधा जी ने गहरी दृष्टि से कृष्ण को देखा और कहा, “कृष्ण, तुम यह प्रेम और यह

विरह कभी नहीं समझ पाओगे। अगर तुम राधा होते, तभी जान पाते।” यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। इसमें उस प्रेम का संकेत था, जो देने में पूर्ण है, जो विरह में भी आनंद खोज लेता है।

कृष्ण ठिठक गए। ईश्वर होकर भी उनके भीतर जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने पूछा, “यदि मैं राधा होता और तुम कृष्ण होतीं, तो क्या करतीं?” राधा जी बोलीं, “यदि मैं तुम्हें अपने विरह में तड़पते देखती, तब मुझे भी तुम्हारी तरह अत्यंत आनंद की अनुभूति होती।” यह उत्तर सुनकर कृष्ण समझ गए कि प्रेम केवल मिलने का सुख नहीं है, बल्कि विरह में भी एक अद्भुत रस है, जिसे केवल प्रेम करने वाला ही जान सकता है।

तभी श्रीकृष्ण ने वह रहस्य प्रकट किया, जो आगे चलकर भक्ति परंपरा की आत्मा बन गया। उन्होंने कहा, “राधा, यदि ऐसा है, तो मैं कलियुग में चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा। मेरा शरीर कृष्ण का होगा, लेकिन मेरी मानसिकता राधा की होगी। मैं राधाभाव लेकर अवतरित होऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रेम कैसा है, जो तुम मुझसे करती हो।”

कृष्ण ने स्वीकार किया कि उनके भीतर तीन इच्छाएं अधूरी हैं। पहली इच्छा यह जानने की कि श्रीराधा का उनके प्रति जो अद्वितीय प्रेम है, उसकी महिमा और स्वरूप क्या है। वह प्रेम कैसा है, जो स्वयं भगवान को भी बांध लेता है। दूसरी इच्छा यह समझने की कि उस प्रेम के माध्यम से राधा उनके जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं, वह माधुर्य वास्तव में कैसा है। और तीसरी इच्छा यह अनुभव करने की कि उनके माधुर्य का आस्वादन करने से राधा को जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख कितना गहरा और दिव्य है।

यही तीन इच्छाएं थीं, जिन्होंने भगवान को भक्त बनने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि कलियुग में श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए—कृष्ण का स्वरूप, लेकिन राधा का भाव। उस अवतार में भगवान स्वयं अपने नाम का कीर्तन करते हैं, स्वयं रोते हैं, स्वयं प्रेम में डूबते हैं और संसार को यह सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग शक्ति, ज्ञान या तर्क नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम है।

राधा-कृष्ण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में अहंकार नहीं होता। यहां तक कि ईश्वर भी जब प्रेम को पूरी तरह जानना चाहते हैं, तो वे प्रेमिका का भाव धारण करने से नहीं हिचकते। राधाभाव में अवतरित होकर कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी प्रेम में मिट जाती है। जहां प्रेम पूर्ण होता है, वहां ईश्वर भी साधक बन जाते हैं।

यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह हर उस हृदय के लिए संदेश है, जो प्रेम को समझना चाहता है। राधा का प्रेम और कृष्ण का चैतन्य रूप यह बताता है कि प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप वही है, जहां देने में ही आनंद है, विरह में भी रस है और जहां स्वयं ईश्वर भी प्रेम को जानने के लिए भक्त बन जाते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

## अटल नेतृत्व, अविरत विकास : सुशासन से समृद्ध किसान

# किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई) अंतर्गत राज्य के 98 प्रतिशत से अधिक गाँवों को मिल रही है दिन में बिजली, 19 लाख से अधिक किसान प्राप्त कर रहे हैं दिन में बिजली का लाभ

- वर्ष 2026-27 में जेटको द्वारा 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 नए सबस्टेशन बनाने तथा लगभग 1100 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना
- 40 नए सब स्टेशनों, 4640.73 सीकेएम की ट्रांसमिशन लाइन्स तथा 3927.72 सीकेएम के एमवीसीसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च
- मार्च-2026 तक राज्य के सभी किसानों को सिंचाई के दिन में बिजली मिलने लगेगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुशासन का उद्देश्य किसानोन्मुखी योजनाओं और पहलों को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुँचाना है। किसान भारत की रीढ़ हैं और भारत का विकास तभी संभव है; जब किसान समृद्ध, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर हों। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सुदृढ़ सुशासन अंतर्गत राज्य सरकार किसानोन्मुखी योजनाएँ सभी किसानों तक सफलतापूर्वक पहुँचा रही है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई), जिसके जरिये आज राज्य के 17,018 गाँवों यानी 98.66 प्रतिशत गाँवों को दिन में बिजली का लाभ मिल रहा है। इस योजना अंतर्गत गुजरात के 19.69 लाख किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति करने की गुजरात की सफलता के विषय में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल कहते हैं, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कृषि हितकारी नीतियों एवं किसानों के प्रति संवेदना के कारण आज राज्य के लगभग 98 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। जो बाकी हैं, उन्हें भी मार्च-2026 दिन में बिजली मिलने लगेगी और यह मिशन पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का यह एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिसे हम पूरा कर सके। यह हम सबके लिए आनंद की बात है। किसानों को पर्याप्त पानी तथा बिजली मिलने के कारण राज्य के कृषि क्षेत्र की तसवीर समग्रतया बदल गई है और किसान समृद्ध हुए हैं।"

### किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत सूर्य प्रकाश के घण्टों का अधिकतम् उपयोग हो; इस प्रकार किसानों को बिजली दी जाती है

किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई) वर्ष 2020 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य सुबह 5 से रात 9 बजे तक दो स्लॉट में (सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक का स्लॉट तथा दोपहर 1 से रात 9 बजे तक का स्लॉट) में विद्युत आपूर्ति करना था। हालाँकि योजना लागू किए जाने के बाद कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत आपूर्ति की समयसारिणी को सूर्य प्रकाश के घण्टों के हिसाब से अधिक कार्यक्षम बनाया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ, जिससे सिंगल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट प्रकाश में आया। इस कॉन्सेप्ट के तहत किसानों को सूर्य प्रकाश के घण्टों के दौरान; विशेषकर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक कृषि के लिए बिजली पहुँचाई जाती है। सौर ऊर्जा को इस प्रकार एकीकृत किए जाने से अधिक मांग की समयावधि के दौरान ग्रिड पर लोड कम होता है, जिससे कृषि के लिए टिकाऊ एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होती है। हाल में इस योजनांतर्गत राज्य के 17,018 गाँवों (98.66 प्रतिशत) को दिन में बिजली पहुँचाई जा रही है और राज्य के 98 प्रतिशत सबस्टेशनों को डे-टाइम यानी दिन के समय में शिफ्ट किया गया है। शेष 231 गाँवों को इस योजनांतर्गत लाने के लिए शेष 45 रोटेशनल सबस्टेशनों की शिफ्टिंग का कार्य प्रगत्याधीन है। उल्लेखनीय है कि इस योजनांतर्गत 40 नए सबस्टेशन स्थापित करने, 4640.73 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की ट्रांसमिशन लाइनें डालने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3927.72 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के एमवीसीसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 5353.62 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया गया है।

### दिन में बिजली मिलने से जानवरों का भय दूर हुआ, समय की भी बहुत बचत हुई : किसान सूर्योदय योजना के लाभार्थी

हिम्मतनगर तहसील के काँकरोल गाँव के किसान श्री जयेश पटेल, जो हिम्मतनगर मंडी के अध्यक्ष भी हैं, कहते हैं, "पहले किसानों को रात में बिजली मिलती थी, जिसके कारण रात में पानी छोड़ने जाने में तकलीफ होती थी। पानी का व्यय भी बहुत होता था और रात में जानवरों का भी डर रहता था। अब किसान सूर्योदय योजना अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से हमें दिन में बिजली मिलती है, जिसके माध्यम से इन सभी समस्याओं का निवारण आ गया है। अब किसानों को खेतों में उचित समय पर उचित मात्रा में पानी मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का समग्र हिम्मतनगर तहसील के किसानों की ओर से आभार मानता हूँ।" उल्लेखनीय है कि किसान सूर्योदय योजना के क्रियान्वयन से किसानों को दिन में बिजली मिलने के कारण वे दिन के दौरान उचित समय पर खेत में अच्छी तरह सिंचाई कर पाते हैं और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं, जो किसानों की आर्थिक समृद्धि में परिणामित होता है। ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निरंतर सुदृढ़ीकरण के साथ राज्य सरकार किसान सूर्योदय योजना का चरणबद्ध क्रियान्वनय जारी रखेगी, जो दिन के समय विश्वसनीय एवं टिकाऊ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

### वर्ष 2026-27 में नए सबस्टेशन स्थापित करने तथा ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने की योजना

वर्ष 2026-27 में दिन के दौरान कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (जेटको) ने लगभग पाँच सबस्टेशनों तथा 1100 सीकेएम ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना है, जिसका अनुमानित खर्च 1000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त; वर्ष 2026-27 में डिसकॉम के लिए एबी केबल/एमवीसीसी डालने का अनुमानित खर्च 375 करोड़ रुपए है।

# महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने वडोदरा मंडल के दो कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

**(जीएनएस)**। रेलवे के संचालन में संरक्षा सर्वोपरि होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की सजगता एवं सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वडोदरा मंडल के दो रेल कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार नवम्बर 2025 के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए सतर्कता दिखाने और संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते टालने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदान किए गए।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी (1) श्री नंदन कुमार ठाकुर, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के पखाजन में स्टेशन मास्टर,के पद पर कार्यरत हैं।दिनांक 22.11.2025 को, अपने स्टेशन से लगभग 19:15 बजे गुड्स ट्रेन के गुजरते समय, उन्होंने ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति देखी, जो लाल तपे पहिये और जलने की गंध से स्पष्ट थी। तत्परता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दशति हुए उन्होंने तुरंत लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर को VHF संचार के माध्यम से सूचित किया। उनकी समय पर दी गई सूचना के आधार पर ट्रेन को रोका गया, समस्या की जाँच की गई तथा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या का सफलतापूर्वक निवारण किया गया। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक संभावित दुर्घटना टल गई तथा ट्रेन संचालन सुरक्षित रूप से सुनिश्चित हो सका।

(2) श्री मुकराज मीणा 'गोधरा' में लोको पायलट (मालगाड़ी), के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 14.10.2025 को, गोधरा से गुड्स ट्रेन पर काम करते समय, ववादी खुर्द –टिम्बा रोड के बीच, लोको पायलट ने देखा कि OHE तार टूटी हुई अवस्था में लटका हुआ था। अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ के साथ उन्होंने तुरंत इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबाया, पेंटोग्राफ को नीचे किया और फ्लैशर लाइट चालू की, जिससे ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक गई। इसके बाद उन्होंने स्टेशन मास्टर- टिम्बा रोड और TRD स्टाफ के माध्यम से TLC/CTO को सूचित किया, जिन्होंने आकर पुष्टि की कि OHE स्टे ट्यूब इंसुलेटर टूटा हुआ था। सुधार के बाद, सेक्शन को आगे की आवाजाही के लिए तैयार कर दिया गया।उनकी पैनी नज़र, समय पर की गई कार्रवाई और त्वरित निर्णय के कारण, पेंटोग्राफ और OHE को और अधिक नुकसान से सफलतापूर्वक बचा लिया गया, जिससे लोकोमोटिव की सुरक्षा और निर्बाध ट्रेन आवाजाही सुनिश्चित हुई।

महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

पश्चिम रेलवे को अपने ऐसे कर्मचारियों पर गर्व है, जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी के साथ कार्य करते हैं और रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना है, बल्कि यह पश्चिम रेलवे की उस संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करता है, जहाँ संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

# पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने अहमदाबाद मंडल के तीन कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में अहमदाबाद मंडल के तीन कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए "मैन ऑफ द मन्थ" (नवंबर–2025) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित कर्मचारी है—

1. श्रीमती भावना साकरे, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, साबरमती दिनांक 28.11.2025 को श्रीमती भावना साकरे - ट्रेन संख्या AFGB/MIGK पर लोको संख्या 50001 के साथ ड्यूटी पर थीं। सुबह लगभग 09:05 बजे साबरमती यार्ड में सिग्नल S12 पर खड़ी ट्रेन के पास से 'रेल स्पेशल रतनगढ़' (लोको संख्या 60386) गुजर रही थी। इस दौरान उन्होंने चार स्थानों पर रेल पटरी (LWR) में खिसकाव देखा, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत वॉकी-टॉकी के माध्यम से संबंधित लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर से संपर्क कर ट्रेन को रुकवाया। निरीक्षण में पटरी असुरक्षित पाई गई, जिससे समय रहते संभावित पटरी से उतरने, बड़े हादसे तथा जान-माल के नुकसान को टाल दिया गया।

2. श्री कृष्ण कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–II, अहमदाबाद

दिनांक 08.11.2025 को ट्रेन संख्या 19412 के लिए लोको संख्या 22392 का ट्रिप निरीक्षण किया जा रहा था। ELS/अहमदाबाद में रूफ एवं ग्रेविटी वर्क सेंटर पर कार्यरत श्रीकृष्ण कुमार ने सूक्ष्म निरीक्षण के दौरान पीटी-2 लोअर आर्म का बेयरिंग बोल्ट टूटी अवस्था में पाया। उनकी सतर्कता एवं गहन जांच से संभावित लोको विफलता, ट्रेन डिटेंशन तथा ओएचई को होने वाले नुकसान को समय रहते रोका जा सका।

3. श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर, ट्रेक मेंटेनर, साणंद

श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर, SSE/P. Way/साणंद के अंतर्गत गैंग नंबर–05 में ट्रेक मेंटेनर के रूप में कार्यरत हैं। दिनांक 02.11.2025 को LC संख्या–29 (छारोडी–साणंद के बीच) पर गेटमैन ड्यूटी के दौरान उन्होंने ट्रेन संख्या 16333 से धुआँ निकलते देखा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तुरंत लाल झंडा दिखाकर ट्रेन रुकवाई। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात ब्रेक ब्लॉक रिलीज किए जाने पर ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे रवाना किया गया।

अहमदाबाद मंडल को अपने ऐसे कर्मठ, सजग और जिम्मेदार कर्मचारियों पर गर्व है। यह सम्मान न केवल उनकी कर्तव्यपरायणता की सराहना है, बल्कि पश्चिम रेलवे की उस कार्य-संस्कृति का भी प्रतीक है, जिसमें संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

## भावनगर मंडल में टिकट चेकिंग से एकल EFT के माध्यम से अब तक की सर्वाधिक वसूली

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के अंतर्गत टिकट जांच के दौरान एक सराहनीय एवं ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। श्री राजन कुमार सिंह, मुख्य टिकट निरीक्षक(CTI)/वेरावल, ने टी.एन.सी.आर. के रूप में गाड़ी संख्या 12945 (वेरावल–बनारस एक्सप्रेस) के अपर क्लास में कार्य करते हुए 3AC कोच B2 एवं B4 में यात्रियों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितता का पता लगाया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया की गहन चेकिंग के बाद यह पाया गया कि 54 यात्रियों के ग्रुप में 36 यात्री बिना वैध टिकट अथवा अन्य व्यक्तियों के नाम पर यात्रा कर रहे थे। श्री राजन कुमार सिंह ने अत्यंत सूझबूझ, धैर्य एवं कुशल व्यवहार के साथ यात्रियों से बातचीत कर रेलवे नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की तथा 78,060/- (अठहत्तर हजार साठ रुपये मात्र) की रेलवे देय राशि की सफलतापूर्वक वसूली की।

उल्लेखनीय है कि श्री राजन कुमार सिंह दिव्यांग (श्रवण बाधित) हैं और इसके बावजूद उन्होंने ट्रेन में एकल रूप से कार्य करते हुए यह पूरी कार्रवाई स्वयं संपन्न की। उनका यह कार्य न केवल कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का उदाहरण है, बल्कि अन्य रेलकर्मियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि भावनगर मंडल में अब तक किसी भी टीटीई द्वारा एकल लेन-देन (Single EFT) में की गई यह सर्वाधिक वसूली है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा की रेल प्रशासन श्री राजन कुमार सिंह के इस उत्कृष्ट, साहसिक एवं अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

# "द यश मंगलम शो" की नई लघु फिल्म "द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स" गणित के जादूगर रामानुजन को समर्पित',"राष्ट्रीय गणित दिवस" पर हुआ लघु फिल्म का लोकार्पण'

**(जीएनएस)**। मुंबई। इंटरनेट के लोकप्रिय माध्यम यू-ट्यूब पर पिछले दिनों जारी विभिन्न लघु फिल्मों को मिली निरंतर सफलता के बाद सृजनात्मक उत्कृष्टता के एक सशक्त ब्रांड के रूप में लोकप्रिय होते जा रहे *"द यश मंगलम शो"* की नवीनतम कड़ी के रूप में लघु फिल्म *"द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स"* का लोकार्पण राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 21 दिसम्बर, 2025 को बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत बिहार फिल्म विकास निगम के मुख्य सलाहकार अरविंद रंजन दास द्वारा किया गया। इस लघु फिल्म में गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व का सुरुचिपूर्ण विश्लेषण किया गया है।

एक अनूठी सृजनात्मक पहल के अंतर्गत *"वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई"* द्वारा *"मगध एकेडमी ऑफ कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स" MACPA* के बैनर तले नवसृजित यह अद्भुत लघु फिल्म

*"द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स"* सोशल मीडिया के सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब पर एक सुरुचिपूर्ण चैनल *"द यश मंगलम शो-2025'* के अंतर्गत अपलोड की गई है, जो अपने अनूठे कंटेंट और प्रस्तुतीकरण के विलक्षण अंदाज़ के लिए काफी लोकप्रिय है और व्यापक तौर पर सराहा जाता रहा है। इससे पहले इस लोकप्रिय शो की *"धरोहरः ए पोएटिक सागा"*, *"शिल्पकार"*, *"योगा रिट्रीट", "सेहत के रखवाले", *कारगिल विजय दिवस- ए पोएटिक सागा*, *"मैं भारत हूँ..!"* और *"पथ प्रदर्शक"* जैसी प्रभावशाली कड़ियाँ यू-ट्यूब पर काफी अच्छा प्रतिसाद पा चुकी हैं। इस शो के जोशीले प्रस्तुतकर्ता यश मंगलम हैं, जो सिर्फ़ 15 वर्ष की आयु में ही सशक्त प्रस्तुतीकरण से अपनी दमदार शैली की बदौलत शो- बिज़ की दुनिया में अपना अच्छा मुक़ाम हासिल कर रहे हैं। इस विशेष लघु फिल्म का प्रभावशाली लेखन मुंबई के सुपरिचित गीतकार, मंच संचालक तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने किया है, जिसमें गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बखूबी पिरोया गया है। उल्लेखनीय है कि गजानन महतपुरकर द्वारा लिखी गई 10 से अधिक लघु फिल्में पहले ही यू-ट्यूब पर धूम मचा चुकी हैं। इसी क्रम में अब नवीनतम लघु फिल्म के ज़रिये गजानन महतपुरकर की सशक्त लेखनी और सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं एडिटर अनुपम मंगलम के कुशल निर्देशन का कमाल यू-ट्यूब पर लोकप्रिय हो रहा है। इस लघु फिल्म के प्रोड्यूसर बिहार के प्रमुख शिक्षाविद लायन राजीव भार्गव हैं। इस सशक्त, प्रभावशाली और संवेदनशील लघु फिल्म को कुशल निर्देशन के जरिये पर्दे पर उतारने का दायित्व बखूबी निभाया है, मुंबई के विज्ञापन एवं फिल्म जगत के भरोसेमंद निर्देशक अनुपम मंगलम ने, जिनको पिछले 25 सालों में 300 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में बनाने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। इस नवसृजित लघु फिल्म का भावपूर्ण संगीत समीर पखाले ने दिया है। वीडियोग्राफी श्रीकांत, वी एफ एक्स संयोजन गिनीलाल सालुंके, एडिटिंग प्रताप शिंदे, डिज़ाइनिंग एलेक्स बेकर और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कला मंगलम द्वारा सुनिश्चित की गई है। पटना के मशहूर गणितज्ञ आनंद कुमार को समर्पित और टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल, पटना द्वारा प्रायोजित इस लघु फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई ने किया है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में निर्मित इस लघु फिल्म का लोकार्पण और प्रीमियर शो का उद्घाटन बिहार फिल्म विकास निगम के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर अरविंद रंजन दास द्वारा 21 दिसम्बर , 2025 को पटना के टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं लॉयंस क्लब, पटना की अध्यक्ष शिवानी भार्गव और सचिव लॉयन रोहित शंकर सहित अन्य गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस लघु फिल्म में टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अभिनय किया है। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अरविंद रंजन दास उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख अतिथियों में लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रदीप खेतान, लॉयन रचना खेतान, डॉ. रवि भार्गव, बिहार स्टेट पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के अशोक मेहता, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी योगेश गुप्ता, पटना के प्रमुख समाजसेवी नीरज गुप्ता, जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रवण कुमार , डॉ. चिरंजीव दुबे , लायन सोनिया, बाटा के पूर्व HR निदेशक ऋषिकेश मुख्य रूप से शामिल हैं। यह लघु फिल्म इस यू-ट्यूब लिंक पर देखी जा सकती है :-

## कानून से ऊपर कोई नहीं, भीड़तंत्र को नहीं मिलेगी छूट : मुख्यमंत्री विजयन

**(जीएनएस)**। तिरुअनंतपुरम। केरल के पलक्कड़ जिले में सामने आए कथित मॉब लिंचिंग के मामले ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वालयार के कीजक्के अत्तापल्लम क्षेत्र में मूल रूप से छत्तीसगढ़ निवासी रामनारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज के भीतर पनप रही भीड़ मानसिकता की भयावह तस्वीर भी सामने ला दी है। इस घटना पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विजयन ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय करार देते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल जैसी प्रगतिशील और साक्षरता में अग्रणी राज्य में इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। विजयन ने भरोसा दिलाया कि पुलिस की एक विशेष जांच टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जो भी लोग इस घटना में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## 24 से 30 दिसंबर तक साबरमती-खोडियार के बीच,स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 (त्रागढ रोड फाटक) बंद रहेगा

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर साबरमती-खोडियार स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 किमी 773/4-6 (त्रागढ़ रोड फाटक) 24 दिसंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से 30 दिसंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे तक मरम्मत कार्य (AMC रोड एप्रोचिंग और हाइट गेज कार्य) हेतु 7 दिन बंद रहेगा।

सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नंबर 241 अंडरपास वाया गोदरेज गार्डन सिटी और एस. जी. हाईवे से आवागमन कर सकते हैं।

# मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से मंगलवार को गुजरात पुलिस के 11,607 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे

### गांधीनगर स्थित रामकथा मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल की प्रेरक उपस्थिति रहेगी

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के आशय से लोकरक्षक कैडर की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इस भर्ती अंतर्गत चयनित हजारों युवा उम्मीदवारों के लिए 23 दिसंबर, 2025 मंगलवार को गांधीनगर में सेक्टर-11 स्थित रामकथा मैदान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में भव्य 'चयन (नियुक्ति) पत्र प्रदान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस आवास एवं जेल राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहकर नवनियुक्त जवानों को प्रोत्साहित करेंगे। लोकरक्षक कैडर में कुल 11,899 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई थी, जिनमें 8,782 पुरुष एवं 3,117 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। फिलहाल डॉक्टूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण कर चुके 11,607 उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में शेष 13,591 रिक्तियों के लिए भी नया विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। यह नई भर्ती प्रक्रिया भी हाल में कार्यरत है, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवा में जोड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, राज्य पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोटरू सहित उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

# हंसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड: नाबालिग की हत्या के आरोप में नौ दोषी ठहराए गए

**(जीएनएस)**। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हंसखाली में 2022 में हुई नाबालिग लड़की के सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद मौत के मामले में सोमवार को अदालत ने निर्णायक फैसला सुनाया। राणाघाट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस जघन्य अपराध में शामिल नौ आरोपियों को दोषी ठहराया। इस फैसले के बाद पूरे राज्य में न्याय की उम्मीद के साथ ही आक्रोश भी देखा गया। दोषियों को सजा की मात्रा तय करने के लिए अदालत ने मंगलवार, 24 दिसंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। इस मामले की जांच भारतीय केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई ने की थी। प्रारंभ में यह जांच राज्य पुलिस कर रही थी,

लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने सभी साक्ष्यों, घटनास्थल पर मिले सुरागों और गवाहियों का विश्लेषण किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि नौ आरोपियों ने बर्बरता की सारी हदें पार की थीं, और अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन्हें दोषी करार दिया।

**जन्मदिन पार्टी में हुई वारदात**

यह दर्दनाक घटना 4 अप्रैल 2022 को हुई थी। पीड़िता, मात्र 14 वर्ष की नाबालिग लड़की, को कथित तौर पर एक सत्तारूढ़ दल के पंचायत नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी में बुलाया गया। पार्टी में ही आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घिनौनी घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मौत के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए उसके शव का जल्दी में अंतिम संस्कार कर दिया। जांच में यह पाया गया कि शव जलाने की प्रक्रिया पूरी तरह दबाव और डर के माहौल में की गई थी। इस कदम ने न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश को उजागर किया बल्कि पूरे राज्य में गुस्से और विरोध प्रदर्शन को भी भड़का दिया।

**राज्य और राजनीतिक प्रतिक्रिया**

इस घटना की खबर सामने आते ही पश्चिम बंगाल में आक्रोश फैल गया। विपक्षी दलों ने इसे कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता और सत्ता का दुरुपयोग बताया। सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने भी इस मामले में त्वरित न्याय की मांग की। यह मामला राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और प्रशासनिक ढांचा, पुलिस तंत्र और कानून व्यवस्था की जवाबदेही पर प्रकाश डालता है।

टीएमसी नेता के बेटे सहित अन्य दोषियों के नाम उजागर होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इसे सत्ता के संरक्षण में अपराध की कोशिश के रूप में देखा और उच्च न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया।

**न्यायिक प्रक्रिया और भविष्य की सुनवाई**

अदालत ने दोषियों की सजा तय करने के लिए 24 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। इस दौरान दोषियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उनके विरुद्ध तय सजा सुनाई जाएगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा के निर्धारण में इस प्रकार के जघन्य अपराध और पीड़िता की उम्र व शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि ऐसे मामलों में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। पुलिस और प्रशासन ने भी यह आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**सार्वजनिक संदेश और सामाजिक प्रभाव**

हंसखाली कांड ने समाज में गंभीर संदेश छोड़ा है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे राज्य और देश में नाबालिगों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और न्यायपालिका की जवाबदेही की परीक्षा भी है। सामाजिक संगठनों और नागरिकों के लिए यह एक चेतावनी है कि समाज में इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ लगातार जागरूकता और समर्थन बनाए रखना आवश्यक है।

इस जघन्य कांड की वजह से राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा और पुलिस तंत्र में सुधार की मांग और मजबूत हुई है। न केवल न्यायिक प्रणाली को, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को इस तरह की घटनाओं की रोकथाम और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्क और जवाबदेह बनना होगा।

इस मामले की सुनवाई और दोषियों के विरुद्ध सजा के बाद यह निश्चित होगा कि न केवल पीड़िता को न्याय मिलेगा, बल्कि यह पूरे समाज के लिए यह संदेश भी जाएगा कि किसी भी स्तर पर किए गए अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

# इंडियन बैंक घोटाला: करोड़ों रुपये के गबन का आरोपी बैंककर्मी गिरफ्तार, कैशियर को आजीवन कारावास

**(जीएनएस)**। फिरोजाबाद। इंडियन बैंक की जसराना शाखा में करोड़ों रुपये के गबन से जुड़े बहुचर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना जसराना पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

**मामले का विवरण**

यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था, जब इंडियन बैंक के आगरा अंचल कार्यालय में तैनात अंचल प्रबंधक तरुण कुमार विश्नोई ने जसराना थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि शाखा के पूर्व प्रबंधक राघवेंद्र सिंह और कैशियर जयप्रकाश सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खाताधारकों के खातों से करीब 1.86 करोड़ रुपये का गबन किया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अपने कृत्यों को छिपाने के लिए खातों में कई तरह की हेराफेरी करता रहा। यह मामला बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था, जिसके कारण अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

**न्यायालय की कार्रवाई**

पुलिस जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने गंभीर अपराध के आधार पर फैसला सुनाया। कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया। वहीं, अन्य आरोपियों को लंबी अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया।

**फरार आरोपी की गिरफ्तारी**

इस प्रकरण में एक आरोपी सोमिल, निवासी तिलकापुर थाना तालग्राम जनपद कन्नौज, लंबे समय से गिरफ्तारी से बचता चला आ रहा था। उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी के अनुसार, सोमवार को आरोपी को औछा रोड स्थित बड़ा गांव पुल के पास से बुलेट मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई और उसे जेल भेज दिया गया।

**प्रभाव और आगे की कार्रवाई**

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार के धोखाधड़ी मामलों को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सतत निगरानी और जांच जारी रहेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में इस प्रकार के गबन से न केवल ग्राहकों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि वित्तीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। इसलिए अधिकारियों द्वारा आरोपियों को सजा दिलाना एक संदेश है कि पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस मामले में बैंक और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जांच प्रक्रिया को तीव्र गति से पूरा किया और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इससे न केवल प्रभावित खाताधारकों को राहत मिली, बल्कि समाज में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास भी बहाल हुआ।

इस तरह, इंडियन बैंक की जसराना शाखा घोटाले की जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई ने यह साबित किया कि वित्तीय अपराधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना सुनिश्चित किया जाएगा।

# वडोदरा में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर डिश: 100 टन एसी और रोजाना 2000 लोगों का खाना, बिजली बिल जीरो

**(जीएनएस)**। वडोदरा। गुजरात में हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर डिश स्थापित की गई है, जो ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस अल्ट्रा मॉर्डन 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली सोलर डिश की मदद से रोजाना लगभग 2000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा सकेगा और साथ ही 100 टन क्षमता वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चलाया जा सकेगा। इस अनोखी तकनीक से न केवल बिजली और गैस पर निर्भरता कम होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी काफी हद तक घटाया जा सकेगा।

सोलर डिश तकनीक, जिसे 'सोलर कंसंट्रेटर' के नाम से जाना जाता है, सूरज की रोशनी को लेंस या शीशे के माध्यम से एक छोटे पॉइंट पर फोकस कर अत्यधिक तापमान पैदा करती है। इस ताप का उपयोग बिजली उत्पादन (केंद्रित सौर ऊर्जा), इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं और सोलर कुकर के माध्यम से खाना बनाने में किया जा सकता है। वडोदरा की सोलर डिश लगभग सात मंजिला इमारत जितनी ऊंची है और इसमें 300 से अधिक शीशों का उपयोग हुआ है। ये शीशे सूरज की रोशनी को केंद्रित करके उच्च तापमान पैदा करते हैं, जिससे आश्रम और संस्थाओं में स्टीम आधारित खाना पकाने और एयर कंडीशनिंग जैसी

सुविधाएं संचालित की जा सकती हैं।

पहले मुनि सेवा आश्रम में रोजाना 1000 किलो लकड़ी खर्च होती थी, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था बल्कि खर्च भी अधिक होता था। अब सोलर डिश के उपयोग से लकड़ी का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो गया है। आश्रम के डॉक्टर विक्रम मुनि के अनुसार, सोलर डिश द्वारा उत्पन्न स्टीम का इस्तेमाल 100 टन क्षमता वाले एसी सिस्टम, कपड़े धोने, स्टेरिलाइजेशन, गर्म पानी और अन्य जरूरी कामों के लिए किया जाएगा। इससे गैस की जरूरत समाप्त हो जाएगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा।

सोलर डिश का यह विशेष डिजाइन सूरज की दिशा के अनुसार दोनों ओर घूमता रहता है, जिससे इसे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। यह तकनीक आश्रम जैसी संस्थाओं के लिए कम जगह में स्थापित की जा सकती है और संचालन में बेहद आसान है। फिलहाल गोरज में दो सोलर डिश कार्यरत हैं, जिससे कुल 200 टन की एसी क्षमता प्राप्त हो चुकी है।

इस अत्याधुनिक सोलर डिश को भारत में लाने वाले दीपक गढ़िया ने बताया कि इसकी मूल तकनीक ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, लेकिन अब इसका पूरा निर्माण और विकास भारत में किया जा रहा है। यह सोलर डिश केवल खाना बनाने और एसी चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा की लागत को बचाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सोलर टेक्नोलॉजी आने वाले समय में देश के अस्पतालों, आश्रमों, स्कूलों और बड़े संस्थानों में ऊर्जा की लागत घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में अपनाई जा सकती है। यह प्रोजेक्ट भारत में स्वदेशी तकनीक के विकास और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। वडोदरा की यह सोलर डिश न केवल दुनिया की सबसे बड़ी मानी जा रही है, बल्कि यह यह भी दर्शाती है कि नवाचार और तकनीक के माध्यम से ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आश्रम और संस्थाओं के लिए रोजाना 2000 लोगों का खाना बनाने और 100 टन के एसी सिस्टम को चलाने में बिजली का खर्च लगभग शून्य होने की संभावना है, जिससे इसे पर्यावरण और बजट दोनों के लिहाज से अत्यंत लाभकारी प्रोजेक्ट बनाया गया है।

# सोना वायदा में 1949 रुपये और चांदी वायदा में 5341 रुपये का ऊछाल: दोनों वायदे ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचे

**(जीएनएस)**। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में . करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 46552.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 241486.19 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33825 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3185.98 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 39692.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 134899 रुपये के भाव पर खूलकर, 136199 रुपये के ऑल टाइम हाई और 134899 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 134196 रुपये के पिछले बंद के सामने 1949 रुपये या 1.45 फीसदी की मजबूती के साथ 136145 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 1110 रुपये या 1.03 फीसदी की तेजी के संग 108487 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 126 रुपये या 0.94 फीसदी की तेजी के संग 13566 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132600 रुपये के भाव पर खूलकर, 134165 रुपये के दिन के उच्च और 132600 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1717 रुपये या 1.3 फीसदी की तेजी के संग 134144 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132599 रुपये के भाव पर खूलकर, 134364 रुपये के दिन के उच्च और 132599 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132780 रुपये के पिछले बंद के सामने 1500 रुपये या 1.13 फीसदी की तेजी के संग 134280 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 209475 रुपये के भाव पर खूलकर, 214583 रुपये के ऑल टाइम हाई और 209475 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 208439 रुपये के पिछले बंद के सामने 5341 रुपये या 2.56 फीसदी की तेजी के संग 213780 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 5442 रुपये या 2.61 फीसदी की बढ़त के साथ

**क्रूड ऑयल वायदा में 98 रुपये की तेजी : कमोडिटी वायदाओं में 46552.84 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 241486.19 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 39692.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33825 पॉइंट के स्तर पर**

214311 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 5524 रुपये या 2.65 फीसदी की तेजी के संग 214314 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3580.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 7.45 रुपये या 0.67 फीसदी की तेजी के संग 1122.3 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 1.8 रुपये या 0.6 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 303.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.3 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 285.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा बिना बदलाव के 181.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3226.02 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5124 रुपये के भाव पर खूलकर, 5208 रुपये के दिन के उच्च और 5114 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 98 रुपये या 1.92 फीसदी की तेजी के संग 5203 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 97 रुपये या 1.9 फीसदी की तेजी के संग 5202 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 362.2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 371.1 रुपये और नीचे में 361.6 रुपये पर पहुंचकर, 356.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 10.5 रुपये या 2.94 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 367.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 10.2 रुपये या 2.86 फीसदी की मजबूती के साथ 367.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 937 रुपये के भाव पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.13 फीसदी गिरकर 930.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20492.32 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 19200.31 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3035.81 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 259.20 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 18.01 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 267.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 608.04 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2600.69 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 16936 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 80044 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 22075 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 332239 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 36522 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17204 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 42092 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 109323 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22537 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 44520 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 33899 पॉइंट पर खूलकर, 33899 के उच्च और 33365 के नीचले स्तर को छूकर, 601 पॉइंट बढ़कर 33825 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 37.2 रुपये की बढ़त के साथ 170.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 रुपये की बढ़त के साथ 6.85 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 281 रुपये की बढ़त के साथ 692.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1162.5 रुपये की बढ़त के साथ 2610.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 90 पैसे के सुधार के साथ 7.84 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 34 पैसे की नरमी के साथ 1.03 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 52.2 रुपये की गिरावट के साथ 123.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 6.7 रुपये की गिरावट के साथ 4.7 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 172 रुपये की गिरावट के साथ 168 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1558 रुपये की गिरावट के साथ 745 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.76 रुपये की गिरावट के साथ 5.08 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.13 रुपये की गिरावट के साथ 0.18 रुपये हुआ।

# भारत-न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे आर्थिक साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत हुई: फियो अध्यक्ष

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली । 22 दिसंबर, 2025: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन के दूरदर्शी मार्गदर्शन और नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री श्री टॉड मैकक्ले के घनिष्ठ और सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड नौ महीनों में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते ( एफटीए ) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस घोषणा का स्वागत करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ( फियो ) के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि इतने कम समय में भारत-न्यूजीलैंड एफटीए का पूरा होना दोनों देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

लागू होने पर, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें सभी टैरिफ लाइनों पर टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा। यह समझौता किसानों, एमएसएमई, श्रमिकों, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और युवाओं को भी लाभ पहुंचाएगा, जबकि कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए अपार अवसर पैदा करेगा। इंजीनियरिंग और विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित प्रमुख क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। श्री रल्हन ने कहा कि सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए शून्य-शुल्क पहुंच एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करने वाले

क्षेत्रों को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

फियो प्रमुख ने दोहराया कि एफटीए द्विपक्षीय निवेश को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में विशेष रूप से विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवाओं, नवाचार और रोजगार सृजन में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रल्हन ने यह भी कहा कि एफटीए के तहत निवेश प्रतिबद्धता भारत की विकास गाथा में विश्वास का एक शक्तिशाली संकेत है और विनिर्माण विस्तार, नवाचार और रोजगार सृजन में सार्थक योगदान देगी, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। किसानों के कल्याण पर खास ध्यान देते हुए, यह समझौता न्यूज़ीलैंड को भारतीय कृषि निर्यात के लिए नए अवसर खोलता है, जिसमें फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले, अनाज और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना, और न्यूज़ीलैंड की एडवांस्ड कृषि-तकनीकों तक पहुंच जैसी पहल से उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिलेगी। श्री रल्हन ने कहा कि शहद, कीवीफ्रूट और सेब जैसे बागवानी उत्पादों के लिए लक्षित समर्थन स्थायी कृषि विकास को और मजबूत करेगा।

फियो अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह एफटीए न केवल बाजार पहुंच का विस्तार करता है, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो भारतीय किसानों को वैल्यू चेन में आगे बढ़ने और उच्च आय प्राप्त करने में मदद करेगा। घरेलू संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत ने प्रमुख कृषि और संबंधित उत्पादों, जिसमें डेयरी, चीनी, कॉफी, मसाले, खाद्य तेल, कीमती धातु (सोना और चांदी), कीमती धातु स्क्रैप, तांबा कैथोड और रबर-आधारित उत्पाद शामिल हैं, की सुरक्षा की है, जिससे किसानों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह समझौता आईटी एवं आईटीईएस, वित्त, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में भारत के सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलता है। विशेष रूप से, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद काम पर न्यूज़ीलैंड के पहले अनुबंध भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अभूतपूर्व रास्ते बनाते हैं। बढ़ी हुई गतिशीलता प्रावधान, जिसमें वर्किंग हॉलिडे वीजा, अध्ययन के बाद काम के रास्ते और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा का एक समर्पित कोटा शामिल है, भारतीय प्रतिभा के लिए वैश्विक करियर के अवसरों को और सुविधाजनक बनाएगा। श्री रल्हन ने कहा कि सेवाओं, गतिशीलता, छात्र अवसरों और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रगतिशील प्रावधान दूरदर्शी हैं और भारत के कुशल पेशेवरों और युवाओं को बहुत लाभ पहुंचाएंगे।

फियो भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए को पारस्परिक रूप से लाभकारी और भविष्य-उन्मुख समझौता मानता है जो आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और विकसित भारत 2047 के भारत के दीर्घकालिक विजन का समर्थन करेगा।

## मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष नागरिकों की प्रस्तुतियों-शिकायतों के ऑनलाइन निवारण का दिसंबर महीने का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम 24 दिसंबर बुधवार को आयोजित होगा

### 25 दिसंबर गुरुवार को क्रिसमस के सार्वजनिक अवकाश के चलते दिसंबर-2025 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम बुधवार को

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम अंतर्गत दिसंबर-2025 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम 24 दिसंबर बुधवार को आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुए 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कर्यक्रम के अंतर्गत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दिसंबर महीने के चौथे गुरुवार 25 दिसंबर को क्रिसमस के सार्वजनिक अवकाश के चलते दिसंबर-2025 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम 24 दिसंबर बुधवार को आयोजित करने का निर्णय किया है। नागरिक इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ 24 दिसंबर बुधवार सुबह 8 से 11 बजे के दौरान गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल-2 स्थित मुख्यमंत्री की जन संपर्क इकाई में प्रत्यक्ष आकर दे सकेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की प्रस्तुतियों-शिकायतों को सुनेंगे।